Date : 29.05.2017

HIND SECURITIES & CREDITS LIMITED

Regd Off: D - 16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi - 110041
CIN: L74899DL1993PLC056702, Contact No. +91-9899425575, Website: www.supersecurities.in
Email: supersecurities1993@gmail.com, info_hindsecurities@yahoo.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2017

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2017 (Audited)	Year to date figures for current period ended 31.03.2017 (Audited)	Corresponding three months ended in the previous year 31.03.2016 (Audited)
1	Total income from operations (net)	50.57	188.29	24.58
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.01)	(1.25)	(8.67)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.01)	(1.25)	(8.67)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.72)	(0.87)	(5.99)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(0.72)	(0.87)	(5.99)
6	Equity Share Capital	510.05	510.05	510.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continiunig and discontinued operations)			
	(a) Basic:	(0.01)	(0.02)	(0.12)
	(b) Diluted:	(0.01)	(0.02)	(0.12)

Statement of Assests and Liabilities

(Amount in Rs.)

A	EQUITY AND LIABILITIES	As at 31.03.2017 (Audited)	As at 31.03.2016 (Audited)
1	**Shareholders's funds**		
	(a) Share Capital	51,005,000	51,005,000
	(b) Reserve and Surplus	4,377,118	4,464,415
	(c) Money received against share warrants	-	-
	Sub-total- Shareholder's funds	**55,382,118**	**55,469,415**
2	**Share application money pending allotment**	-	-
3	**Minority interest ***	-	-
4	**Non- Current Liabilities**		
	(a) Long-term borrowings	2,175,112	6,531,356
	(b) Deferred tax liabilities (net)	-	-
	(c) Other long-term liabilities	-	-
	(d) Long-term Provisions	-	-
	Sub-total- Non Current Libilities	**2,175,112**	**6,531,356**
5	**Current liabilities**		
	(a) Short-term borrowings	168,050,522	146,882,869
	(b) Trade payables	-	-
	(c) Other current liablities	2,461,500	2,059,823
	(d) Short-term provisions	413,564	372,293
	Sub-Total - Current liabilities	**170,925,586**	**149,314,985**
	Total- EQUITY AND LIABILITIES	**228,482,816**	**211,315,756**
B	**ASSETS**		
1	**Non-Current Assets**		
	(a) Fixed assets	338,455	451,119
	(b) Goodwill on cosolidation*	-	-
	(c) Non-Current investments	-	-
	(d) Deferred tax assets (net)	38,046	-
	(e) Long-term loans and advances	63,459,746	77,072,574
	(f) Other non-current assets	-	-
	Sub-total- Non Current Assets	**63,836,247**	**77,523,693**
2	**Current Assets**		
	(a) Current investments	-	-
	(b) Inventories	12,174,886	12,342,986
	(c) Trade Receivables	-	-
	(d) Cash and Cash equivalents	3,557,611	619,774
	(e) Short-term loans and advances	144,678,964	117,503,778
	(f) Other current assets	4,235,108	3,325,525
	Sub-total-Current Assets	**164,646,569**	**133,792,063**
	TOTAL -ASSETS	**228,482,816**	**211,315,756**

NOTE:

1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for quarter and Financial Year ended March 31, 2017 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The Financial Results are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Amendement Rules, 2016.
3. The above results duly reviewed by the Audit Committee, have been approved by the Board of Directors in its meeting held on May 29, 2017.
4. The full format of the Audited Financial Results are available on the webiste of BSE (www.bseindia.com) and Company's website(www.supersecurities.in).

For Hind Securities and Credits Limited
sd/-
(Jagdish Rai Bansal)
Managing Director (DIN: 00673384)

Place : Delhi
Date : 29.05.2017

नवलवाला बाग

16.06.2017	A/C No: 053800201999952 IFSC Code: CORP0000538
16.06.2017	A/C No: 053800201999952 IFSC Code: CORP0000538
16.06.2017	A/C No: 056400201999952 IFSC Code: CORP0000564
16.06.2017	A/C No: 047900201999952 IFSC Code: CORP0000479
16.06.2017	A/C No: 047900201999952 IFSC Code: CORP0000479
16.06.2017	A/C No. 213200201999952 IFSC Code: CORP0002132

सार समाचार

दिनाकरन के जमानत का विरोध

नई दिल्ली,भाषा। अन्नाद्रमुक (अम्मा) धड़े के नेता टीटीवी दिनाकरन ने एक विशेष अदालत में जमानत मांगी और कहा कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज किये गये हैं, लेकिन चुनाव आयोग के रिश्वतखोरी मामले में किसी सरकारी सेवक को आरोपी नहीं बनाया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उनकी जमानत का पुरजोर विरोध किया और कहा कि उन्होंने दूसरे लोगों के साथ साजिश रचकर भ्रष्ट तरीकों से चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को कमजोर किया। विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने दलीलों पर सुनवाई के बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख तय की। दिनाकरन के साथ 25 अप्रैल की रात को गिरफ्तार किये गये उनके करीबी सहयोगी मल्लिकाजरुन ने भी इस आधार पर जमानत मांगी कि उनके बताये अनुसार कोई धन जब्त नहीं हुआ है और वह पुलिस द्वारा सम्मन नहीं जारी किये जाने के बाद भी जांच में शामिल हुए। अदालत ने दिनाकरन, मल्लिकाजरुन, कथित बिचौलिये सुकेश चंद्रशेखर और कथित हवाला कारोबारी नाथू सिंह की न्यायिक हिरासत 12 जून तक बढ़ा दी। सह-आरोपी ललित कुमार पांच जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। दो घंटे चली सुनवाई के दौरान दिनाकरन की ओर से वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने दलील दी कि पुलिस नेता को हिरासत में रखने के लिए हताश है और उन्हें इस आधार पर जमानत देने से मना नहीं किया जा सकता कि यह गंभीर मामला है।

पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली,वार्ता। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठों राज्यों का समग्र विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता में हैं और इसके लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। डा. सिंह ने यहां पूर्वोत्तर परिषद की 66 वीं सालाना बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नया एजेंडा तय किया है और उस पर पूरी गंभीरता और उत्साह से काम किया जा रहा है।

प्रशासन/राजनीति

मोदी सरकार ने सिर्फ बातें कीं

मायावती ने कहा,केंद्र सरकार विरोधी पार्टियों को राजनीतिक दुश्मन मान रही है।

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने मोदी सरकार की तीन साल की उपलब्धियों को नगण्य बताते हुये कहा है कि बीते तीन सालों में केन्द्र सरकार ने कोई काम नहीं किया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि कहा कि इस सरकार के चौथे वर्ष में देश के करोड़ों लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में उन्हें क्या मिला बल्कि उनके हितों पर हर प्रकार का कुठाराघात ही किया गया है।

बसपा की ओर से जारी मायावती के बयान में मोदी सरकार पर तीन साल की उपलब्धियों को सरकारी विज्ञापनों के जरिये प्रचारित करने के लिये जनता का पैसा पानी की तरह बहाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीते तीन सालों में मोदी सरकार की दलित और अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के कारण न सिर्फ देश में सामाजिक समरसता का तानाबाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है बल्कि गलत आर्थिक नीतियों के कारण अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी ज्यादा बढ गयी है।

मायावती ने कहा कि केन्द्र सरकार के तीन साल के कामकाज का आकलन करने पर साफ महसूस होता है कि समाज के कमजोर और दलित तबके के लोग गरीबी के दुश्चक्र में फंस गए हैं जबकि अमीर वर्ग के लोग लगातार धनाड्य होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में लगातार बढती मंहगाई, बेरोजगारी और जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा मोदी सरकार के देश बदलने के दावों की हकीकत को स्पष्ट करने के लिये काफी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यकों की बदहाली को छुपाने के लिये विकास के बडे बडे दावों को सच साबित करने के लिये सरकारी विज्ञापनों का सहारा ले रही है। इसके लिये सरकार ने विज्ञापनों पर अकूत धन खर्च करने की नीति अपनायी है।

मायावती ने कहा कि पिछले तीन सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ मुठ्ठी भर पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाया है। मायावती ने कहा कि 'गोरक्षा के नाम पर निर्दोष दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भगवा ब्रिगेड का उपद्रव और आतंक मोदी सरकार की ही देन है। इससे जनसामान्य में न्याय की उम्मीद लगातार घट रही है जो देश हित के लिहाज से बेहतर भविष्य के लिये खतरनाक संकेत है।'

गोवधः आरोपी कार्यकर्ता कांग्रेस से निलंबित

तिरुवनंतपुर वार्ता। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी)ने मवेशियों के वध के लिए उनकी बिक्री पर केन्द्र सरकार के प्रतिबंध के विरोध में सार्वजनिक रूप से गाय काटने तथा उसके मांस को पकाकर प्रदर्शनकारियों के बीच बांटने के आरोप में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तीन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया। केपीसीसी के अध्यक्ष एम एम हासन ने यहां संवाददाताओं को बताया कि पार्टी ने युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिजिल मक्कुट्टी और दो कार्यकर्ताओं जोसी कंडातिल तथा शरफुद्दीन को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इन कार्यकर्ताओं ने वध के लिए मवेशियों की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ कन्नूर में प्रदर्शन किया था और इस दौरान उन्होंने गाय का वध करके उस मांस वितरित किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को 'मूर्खतापूर्ण एवं बर्बर 'करार देते हुये इसकी निंदा की थी तथा केपीसीसी पर इन लोगों को पार्टी से निलंबित करने के लिए दबाव बनाया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा ' केरल में कल जो कुछ भी हुआ वह निंदनीय एवं बर्बरतापूर्ण था। यह मुझे एवं कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह अस्वीकार्य है। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं ' इस बीच केरल पुलिस ने भी इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 02 के तहत मामला दर्ज किया है।

लोग बीफ फेस्ट पर खामोश क्यों

लखनऊ, भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वध के लिये पशु बाजार से जानवर खरीदने पर रोक लगाये जाने के विरोध में केरल में 'बीफ फेस्ट' के आयोजन पर सवाल उठाये। योगी ने भाजपा के सहयोगी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में कहा दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटनाओं पर बोलने वाले इस घटना (बीफ फेस्ट) पर मौन क्यों हैं? उन्होंने कहा कि देश में हर षड्यंत्र पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् मुखर होकर सामने आती रही है। राष्ट्रवाद इस देश की मूल परम्परा रही है और अभाविप इसे शुरू से ही अपना रही है।ज्ञातव्य है कि योगी आदित्यनाथ ने गत 19 मार्च को सत्ता में आते ही गौवध पर सख्ती से रोक लगाते हुए अवैध रूप से संचालित किये जा रहे सभी बूचड़खानो को बंद करा दिया था। केन्द्र सरकार द्वारा लगायी गयी पाबंदी के विरोध में केरल में बीफ फेस्ट (गोमांस भोज) आयोजित किये गये थे। युवक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता और उसके साथियों ने कन्नूर में कथित रूप से सार्वजनिक तौर पर एक बछड़े का वध कर दिया था। केरल पुलिस ने बाद में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था।

मोदी सरकार पर शिवसेना का कटाक्ष

मुंबई,भाषा। भाजपा की अहम सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व संप्रग सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का सिर्फ 'उद्घाटन करने या उनका नाम बदलने'का ही काम किया है और उसने अपने तीन साल के शासन में नोटबंदी को छोड़कर कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं की है। राजग सरकार की घटक शिवसेना ने यह भी सवाल उठाया कि उसके तीन साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न में क्या वे आम आदमी और किसान भी शामिल थे, जो नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले लोगों में थे। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में छपे एक संपादकीय में कहा गया कि नोटबंदी के अलावा सरकार ने कुछ भी नया नहीं किया। असम में भूपेन हजारिका ढोला-सदिया पुल और जम्मू-कश्मीर में चेनानी-नाशरी सुरंग का उदाहरण देते हुए संपादकीय में कहा गया, 'कुछ अहम और बड़ी परियोजनाओं की शुरूआत पिछली सरकार ने की थी और उनके उद्घाटन एवं नाम बदलने मात्र का काम पूरे जोर-शोर से किया गया।'पार्टी ने कहा कि बड़े नोटों को बंद कर देने के मोदी सरकार के 'मजबूत एवं महत्वाकांक्षी' कदम ने औद्योगिक गतिविधियों में पंगुता ला दी और आईटी क्षेत्र में इससे बड़े स्तर पर रोजगार में कमी हुई।

मराठी दैनिक ने कहा कि नोटबंदी किसानों के लिए एक झटका साबित हुई। उन्हें खरीफ के मौसम से पहले खेती के लिए रिण प्राप्त करने में मुश्किल हो रही है। नोटबंदी की घोषणा हुए छह माह से अधिक बीत चुके हैं। इस फैसले ने जिला सहकारी बैंकों को बुरी तरह प्रभावित किया। ये बैंक खेती से जुड़े रिणों का अहम स्रोत होते हैं।

इसमें कहा गया कि सरकार शेयर बाजार के आंकड़े बढ़ने से खुश है लेकिन व्यथित किसानों और जिला सहकारी बैंकों की 'तबाही' से उस पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देता। शिवसेना के मुखपत्र ने बड़े नोटों को बंद करने को लेकर रिजर्व बैंक पर भी निशाना साधा।

शिलांग में भाजपा नेता ने सस्ते बीफ का वादा किया

शिलांग ■ वार्ता/डेस्क

देश के कुछ राज्यों में बीफ प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने कहा कि यदि उनकी पार्टी मेघालय में सत्ता में आई तो बीफ पर प्रतिबंध लगाने की बजाय गरीबों के हित में इस की कीमतें घटाई जायेगी। भाजपा नेता बर्नांड मारक ने कहा कि भाजपा न केवल बीफ की कीमतों को नियंत्रित करेंगी बल्कि इसके साथ अन्य मांस की कीमतों को भी काबू में रखेगी। इसके अलावा गारो हिल्स में बूचड़खानों को वैध किया जायेगा। पूर्व उग्रवादी नेता श्री मारक ने यह भी कहा कि मेघालय में ज्यादातर भाजपा नेता बीफ खाते हैं और केन्द्र इसके उपभोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि मेघालय जैसे राज्य विशेषकर गारो हिल्स में बीफ पर प्रतिबंध लगाये जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने दावा किया कि मेघालय में भाजपा नेता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भलीभांति परिचित है और पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर संवैधानिक प्रावधान है। मेघालय में बीफ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार मांस की कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रही जिस कारण लोगों का शोषण हुआ है। भाजपा नेता ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो बूचड़खाने स्थापित किये जाएंगे और मांस की जांच की जायेगी कि वह उपभोग के लिए ठीक है या नहीं तथा कीमतों को नियंत्रित किया जायेगा।

विहिंगम बंदरगाह की जिम्मेदारी मेरी

कन्नूर केरल,भाषा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा कि विहिंगम बंदरगाह परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर करने की पूरी जिम्मेदारी वह लेते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रपट के आधार पर इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश देने पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि 7,525 करोड़ रुपये की इस बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना को चांडी के 2011 में सत्ता में आने के बाद ही गति मिली थी। कैग ने अपनी रपट में कहा है कि इस परियोजना का ठेका देते वक्त राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं रखा गया। केरल के मौजूदा मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराए।

दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री को तलब

तिरूवनंतपुरम ■ भाषा/डेस्क

एक स्थानीय अदालत ने एक महिला के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक तरीके से बात करने के संबंध में पूर्व परिवहन मंत्री ए के शशींद्रन के खिलाफ आज एक मामला दर्ज किया और उन्हें 28 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। एक टेलीविजन चैनल ने मार्च में एक ऑडियो क्लिप प्रसारित किया था जिसमें शशींद्रन एक महिला के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक तरीके से बात करते सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने 26 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल में शुरू हुए एक टेलीविजन चैनल ने आपत्तिजनक तरीके से बात करने वाला ऑडियो क्लिप इसी दिन प्रसारित किया था।

इस मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी वी अनीश कुमार ने शशींद्रन को यहां 28 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश किए जाने को लेकर समन जारी किए जाने का आदेश दिया। टीवी चैनल की महिला मीडियाकर्मी ने राकांपा विधायक शशींद्रन के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि पूर्व मंत्री ने फोन पर कथित रूप से अश्लील बातें करके उसका कथित उत्पीड़न किया। चैनल ने कहा है कि महिला को कथित अश्लील फोन कॉल स्टिंग ऑपरेशन के दौरान किया गया।

इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए एलडीएफ सरकार ने एक विशेष जांच दल गठित किया था। चैनल के सीईओ अजीत कुमार समेत पांच मीडियाकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शशींद्रन ने कहा कि वह अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब अदालत को कोई शिकायत मिलती है तो उसे लेकर स्वाभाविक ही कोई कदम उठाया जाएगा शशींद्रन ने कहा, अब मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं भी पहले जांच का स्वागत किया है।

वध के लिए मवेशियों की वृद्धि पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन

चेन्नई ■ भाषा/डेस्क

द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर रोक के केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ 31 मई को यहां प्रदर्शन करेंगे।

पार्टी ने मुद्दे पर 'चुप्पी'के लिए पलानीस्वामी सरकार पर भी हमला बोला। द्रमुक ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र ने संविधान द्वारा प्रदत्त भोजन के विकल्प के मौलिक अधिकार को 'छीन लिया'है। मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए इसने कहा कि कड़े प्रतिबंधों के चलते तमिलनाडु के एंथियुर मवेशी बाजार में व्यापार प्रभावित हुआ है। विज्ञप्ति में कहा गया कि स्टालिन मुद्दे पर 'केंद्र एवं राज्य सरकार'के खिलाफ यहां जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री के. पलानीसामी ने शनिवार को कहा था कि वह संबंधित अधिसूचना का अध्ययन करने के बाद मवेशियों की बिक्री पर केंद्र की रोक पर टिप्पणी करेंगे।

आरक्षणः राजपूत संगठनों से एकजुटता की अपील

अहमदाबाद ■ भाषा/डेस्क

राजस्थान स्थित 'श्री राजपूत करणी सेना'ने आरक्षण की मांग करते हुए सभी राजपूत संगठनों से एक बैनर के नीचे आने की अपील की ताकि आर्थिक स्थिति को आरक्षण का लाभ देने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड बनाने के लिए केंद्र सरकार पर 'दबाव' बनाया जा सके। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आरक्षण की मांग के लिए इस साल के अंत तक 15 लाख राजपूत दिल्ली में एकत्र होंगे।

यह संगठन पिछले कुछ वषरें से राजपूतों और अन्य अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलत करता रहा है। चुनावी प्रदेश गुजरात में अपने संगठन का आधार बढ़ाने के प्रयासों के तहत राज्य के दौरे पर आये मकराना ने कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था अपने उदेश्य को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विभिन्न राज्यों में कई राजपूत संगठन हैं जो आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ अपना आंदोलन चला रहे हैं। अब हम ऐसे सभी राज्य निकायों को करणी सेना के बैनर तले लाना चाहते हैं ताकि हम एकजुट होकर संघर्ष कर सकें और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बना सकें। उन्होंने कहा, हम दृढ़ता से मानते हैं कि अनारक्षित श्रेणी के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

आर्थिक स्थिति को आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मापदंड बनाया जाना चाहिए। केंद्र पर दबाव बढ़ाने और इस संबंध में कानून पारित कराने के लिए हमने दिल्ली में इस साल के अंत में 15 लाख राजपूतों की एक विशाल जनसभा की योजना बनाई है।

मकराना ने स्पष्ट किया कि करणी सेना राजपूतों के लिए आरक्षण अन्य समुदायों की कीमतों पर नहीं चाहती जिन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, हम राजपूतों और अन्य जातियों के लिए आर्थिक स्थिति आधारित आरक्षण चाहते हैं। उसके लिए सरकार को कानून पारित करने की आवश्यकता है ताकि आरक्षण के मौजूदा प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और इसे 50 फीसदी की सीमा से आगे ले जाया जा सके। सरकार को इसके लिए बाध्य करने के लिए हम दिल्ली में अपनी ताकत दिखाएंगे।

अस्पतालों के खर्च का आकलन

नई दिल्ली, वार्ता। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे की अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति की आगामी दो जून की बैठक में दिल्ली के दो बड़े सरकारी अस्पतालों राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग को आवंटित राशि के खर्च से जुड़े मामलों की समीक्षा होगी। इसमे राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा उसे आवंटित राशि तथा चिकित्सा उपकरणों का पूरा इस्तेमाल नहीं किए जाने तथा सफदरजंग को अधिकृत सीमा से अधिक राशि जारी किए जाने के बारे में केन्द्रीय महालेखा परीक्षक की स्वास्थ्य मंत्रालय पर तैयार रिपोर्ट के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी।

प्रादेशिक समाचार

घड़ियाली आंसू बहा रहे नीतीश

पटना ■ भाषा/डेस्क

बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से प्रदेश को हुए वित्तीय नुकसान के आलोक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष दर्जे की मांग पर कहा कि 14वें वित्त आयोग के नाम पर श्री कुमार केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री यादव ने यहां कहा कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों में जब केन्द्र की कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने राज्य के साथ हकमारी की तो श्री कुमार की जुबान बंद थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 14वें वित्त आयोग में पिछली

अनुशंसा की तुलना में 136 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया तो मुख्यमंत्री हकमारी का घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि श्री कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बार फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग दुहरायी है। मुख्यमंत्री ने पत्र की प्रति कल मीडिया में जारी की जिसमें कहा गया है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अंतरित किये जाने वाले हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किये जाने की अनुशंसा को आधार बनाते हुये केंद्रीय बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को दी जाने वाली राशि में काफी कमी की गई, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बिहार पर अधिक पड़ा है।

उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारशों के विरुद्ध बिहार को मिलने वाली अंतरित कर की राशि में कमी आई है। वर्ष 2015-16 में 7400 करोड़ रुपये और वर्ष 2016-17 में लगभग 6000 करोड़ रुपये की कमी आई है। इस प्रकार दो वर्ष में कुल 13400 करोड़ रुपये की कमी आई है। उन्होंने कहा, "इस पृष्ठभूमि में हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है।"

भाजपा नेता ने कहा कि बिहार का विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सूची में है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र ने वर्ष 2015-20 के लिए 3.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कांग्रेस नीत संप्रग सरकार द्वारा वर्ष 2010-15 के लिए किये गये 1.60 लाख करोड़ के प्रावधान से करीब ढाई गुना से अधिक है।

रोजगार के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवा

पटना.वार्ता। बिहार के उप मुख्मयंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के युवा नेता तेजस्वी यादव ने देश में नये रोजगार के संबंध में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आज कहा कि इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दावे परस्पर विरोधी हैं ऐसे में जनता तय करे कि इनमें से कौन झूठा है। श्री यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से छपी खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया, केन्द्र की भाजपा सरकार कहती है कि हमारे आने से नौकरियाँ 84 प्रतिशत घट गई। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कहती। तो सबसे झूठा कौन .. भाजपा या भाजपा नीत केन्द्र की सरकार।

HIND SECURITIES & CREDITS LIMITED

Regd Off: D - 16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi - 110041
CIN: L74899DL1993PLC056702, Contact No. +91-9899425575, Website: www.supersecurities.in
Email: supersecurities1993@gmail.com, info_hindsecurities@yahoo.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2017

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2017 (Audited)	Year to date figures for current period ended 31.03.2017 (Audited)	Corresponding three months ended in the previous year 31.03.2016 (Audited)
1	Total income from operations (net)	50.57	188.29	24.58
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.01)	(1.25)	(8.67)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.01)	(1.25)	(8.67)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.72)	(0.87)	(5.99)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(0.72)	(0.87)	(5.99)
6	Equity Share Capital	510.05	510.05	510.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continiunig and discontinued operations) (a) Basic: (b) Diluted:	(0.01) (0.01)	(0.02) (0.02)	(0.12) (0.12)

Statement of Assests and Liabilities (Amount in Rs.)

A	EQUITY AND LIABILITIES	As at 31.03.2017 (Audited)	As at 31.03.2016 (Audited)
1	**Shareholders's funds**		
	(a) Share Capital	51,005,000	51,005,000
	(b) Reserve and Surplus	4,377,118	4,464,415
	(c) Money received against share warrants	-	-
	Sub-total- Shareholder's funds	**55,382,118**	**55,469,415**
2	**Share application money pending allotment**	**-**	**-**
3	**Minority interest ***	**-**	**-**
4	**Non- Current Liabilities**		
	(a) Long-term borrowings	2,175,112	6,531,356
	(b) Deferred tax liabilities (net)	-	-
	(c) Other long-term liabilities -	-	
	(d) Long-term Provisions	-	-
	Sub-total- Non Current Libilities	**2,175,112**	**6,531,356**
5	**Current liabilities**		
	(a) Short-term borrowings	168,050,522	146,882,869
	(b) Trade payables	-	-
	(c) Other current liablities	2,461,500	2,059,823
	(d) Short-term provisions	413,564	372,293
	Sub-Total - Current liabilities	**170,925,586**	**149,314,985**
	Total- EQUITY AND LIABILITIES	**228,482,816**	**211,315,756**
B	**ASSETS**		
1	**Non-Current Assets**		
	(a) Fixed assets	338,455	451,119
	(b) Goodwill on cosolidation*	-	-
	(c) Non-Current investments	-	-
	(d) Deferred tax assets (net)	38,046	-
	(e) Long-term loans and advances	63,459,746	77,072,574
	(f) Other non-current assets	-	-
	Sub-total- Non Current Assets	**63,836,247**	**77,523,693**
2	**Current Assets**		
	(a) Current investments	-	-
	(b) Inventories	12,174,886	12,342,986
	(c) Trade Receivables	-	-
	(d) Cash and Cash equivalents	3,557,611	619,774
	(e) Short-term loans and advances	144,678,964	117,503,778
	(f) Other current assets	4,235,108	3,325,525
	Sub-total-Current Assets	**164,646,569**	**133,792,063**
	TOTAL -ASSETS	**228,482,816**	**211,315,756**

NOTE:
1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for quarter and Financial Year ended March 31, 2017 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The Financial Results are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind- AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Amendement Rules, 2016.
3. The above results duly reviewed by the Audit Committee, have been approved by the Board of Directors in its meeting held on May 29, 2017.
4. The full format of the Audited Financial Results are available on the webiste of BSE (www.bseindia.com) and Company's website(www.supersecurities.in).

For Hind Securities and Credits Limited
sd/-
(Jagdish Rai Bansal)
Managing Director (DIN: 00673384)

Place : Delhi
Date : 29.05.2017